

# अंबानी के “वनतारा” की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चेलमेश्वर के नेतृत्व वाली एसआईटी को 12 सितम्बर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 26 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात स्थित अनंत अंबानी द्वारा स्थापित ‘वनतारा’ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया है। अदालत ने कहा कि सामान्यतः ऐसे आरोपों पर आधारित याचिका, जिनके समर्थन में कोई ठोस सबूत न हो, कानून की दृष्टि में विचारणीय नहीं होती और प्राथमिक स्तर पर ही खारिज की जानी चाहिए।

इसके बावजूद, कोर्ट ने मामले की तथ्यात्मक जांच पड़ताल के लिए जांच आवश्यक मानी है और एसआईटी को 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर करेंगे और आयोग के अन्य

- सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट जया सुकीन व देव शर्मा की याचिका पर दिए जिनमें अखबारों में छपी खबरों के आधार पर पशु अधिकारों के हनन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
- कोर्ट ने एसआईटी गठित करते समय हालांकि यह भी कहा, कि जिन आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस सबूत न हों वे याचिकाएं खारिज कर दी जानी चाहिए पर इस मामले से तथ्यात्मक जांच जरूरी है।
- वनतारा असल में वन्यजीवों का पुनर्वास केन्द्र है जहां देश विदेश से जंगली जानवर लाए जाते हैं। इस केन्द्र की स्थापना अनन्त अंबानी ने की है।

सदस्य होंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले तथा अतिरिक्त आयुक्त, कस्टम्स अनीश गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पंकज मिथल और पीबी वराले की बैंच ने यह

याचिकाओं में लगाए गए आरोप अखबारों में छपी रिपोर्टों पर आधारित हैं और उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए। फिर भी, अदालत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करने की बजाय, एक तथ्यान्वेषण जांच का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने से जिन मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी है, उनमें शामिल हैं: वनतारा द्वारा भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों का अधिग्रहण किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया से किया गया।

क्या ये गतिविधियाँ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तथा चिड़ियाघर नियमों के अनुरूप हैं? क्या जानवरों या उनके उत्पादों के व्यापार संबंधी नियमों का पालन किया गया है? क्या वहां पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल और पशु कल्याण से संबंधित मानकों का पालन हो रहा है?

## वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में 6 की मौत

जम्मू, 26 अगस्त। जम्मू के पास कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मार्ग में अर्धकुवारी के पास मंगलवार को भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गयी और 14 अन्य घायल हो गये हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्रावन बोर्ड ने यह जानकारी दी।

श्राइन बोर्ड ने कहा कि अर्धकुवारी के पास हुए इस भूस्खलन में घायल हुए लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर जम्मू के सभी स्कूल बुधवार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों ने राहत और

- श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई।

बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर माता वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अर्धकुवारी से भवन तक का मार्ग बंद कर दिया गया है। निचले ट्रंक से भी श्रद्धालुओं की आवाजहोी सीमित कर दी गई है। जम्मू प्रशासन ने खराब मौसम और क्षेत्र भर में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूल कल बंद रखने का निर्देश दिया है।

## विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 28 को

जयपुर, 26 अगस्त। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र की बैठकें 1 सितम्बर से आरंभ होंगी। इससे पहले विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने, 28 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे विधान सभा में अपने कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के

- विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने यह परम्परा शुरू की थी।

मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है।

देवनानी ने विधान सभा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद लोकसभा की तर्ज पर विधान सभा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने का निर्णय लिया था। राजस्थान विधान सभा में पहली बार सोलहवीं विधान सभा से आरंभ हुई यह सर्वदलीय बैठक चौथी बार हो रही है।

# एससीओ समिट में मोदी और पुतिन का स्वागत खुद करेंगे जिनपिंग

शी इस कदम से ट्रंप को कड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि टैरिफ वॉर में “ग्लोबल साउथ” एकजुट है

**-डॉ. सतीश मिश्रा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 26 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों और अन्य साझेदारों पर टैरिफ युद्ध थोपने की पृष्ठभूमि में, ग्लोबल साउथ की एकजुटता का संदेश देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन, चीन में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेंगे। यह कदम वांशिंगटन को एक सूक्ष्म किंतु स्पष्ट संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है।

शी जिनपिंग अगले सप्ताह चीन में एक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच पर 20 से अधिक विश्व नेताओं को इकट्ठा करेंगे, जिससे न केवल ट्रंप के समय ग्लोबल साउथ की शक्ति का प्रदर्शन होगा, बल्कि प्रतिबंधों से जुझ रहे रूस को एक और कूटनीतिक जीत पाने में मदद मिलेगी।

पुतिन और मोदी के अलावा, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के नेताओं को भी

- चीन में हो रहे तियानजिन समिट में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं। 7 सालों में उनकी यह पहली चीन यात्रा है और भारत और चीन के बीच गंभीर सीमा विवाद को देखते हुए भी यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
- चीन भी चाहता है कि भारत अमेरिका के पाले में ना जाए क्योंकि एक स्वतंत्र तटस्थ भारत का चीन के साथ आना उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

आमंत्रित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन भारत और चीन के बीच 2020 को यातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है, क्योंकि अब भारत पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

पिछले साल कज़ान, रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मोदी, शी और पुतिन ने मंच साझा किया था, जबकि उस समय पश्चिमी नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन से दूरी बना रखी थी। नई दिल्ली में रूसी दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में कहा कि मास्को को शी जिनपिंग और मोदी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की उम्मीद है। चीनी राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन

को एक ऐसे मंच के रूप में पेश करना चाहेंगे जो दिखाए कि अमेरिका के नेतृत्व से रहित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी हो सकती है और यह भी जनवरी तक वाइट हाउस ने चीन, ईरान, रूस और अब भारत पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चाइना-ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के संपादक एरिक ओलेंडर ने कहा, जरा देखिए ब्रिक्स ने डॉनल्ड ट्रंप को कितना विचलित किया है – यही तो इन मंचों की मूल भूमिका है। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन एससीओ के 2001 में गठन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसे “अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नई

प्रकार की संरचना में एक महत्वपूर्ण शक्ति” बताया। हाल के वर्षों में भारत की नीति अमेरिका और इज़रायल के प्रति शुकाव के कारण एससीओ और ब्रिक्स के प्रति थोड़ी ठंडी पड़ी थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के घमकाने की नीति भारत तथा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति असम्मानजनक रवैये ने भारत को इन मंचों की ओर फिर से आकर्षित किया है। सुरक्षाकारणों से गठित एससीओ, जो कभी छह यूरोशियाई देशों का समूह था, अब 10 स्थायी सदस्य और 16 संवाद व पर्यवेक्षक देशों तक फैल चुका है। इसका ध्यान अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और सैन्य सहयोग तक भी विस्तारित हो चुका है। हालाँकि विश्लेषकों का मानना है कि एससीओ ने अब तक ठोस सहयोग के नतीजे नहीं दिए हैं, लेकिन चीन के लिए यह अमेरिका के विरुद्ध ग्लोबल साउथ की एकजुटता दिखाने का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। कुछ विशेषज्ञ जो चीन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और अमेरिका भारत संबंध के समर्थक है उनका कहना है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## अमेरिका ने 50% टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी किया

नई दिल्ली, 26 अगस्त। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना को ऐलान कर दिया है। यह वही टैरिफ है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पहले कर चुके हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्यूरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर इसकी रूपरेखा पेश की। यह कदम ऐसे

- नोटिस के अनुसार 27 अगस्त को रात 12.01 के बाद भारत के गोदामों से निकले माल पर यह टैरिफ लगेगा।

समय में उठाया जा रहा है, जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ती नजर आ रही हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा, जो 27 अगस्त, 2025 को सुबह 12:01 बजे (पूर्वी डेलाइट समय) के बाद खपत के लिए आयात (शेष अंतिम पृष्ठ पर )













# ‘कांग्रेस कमीशन देखती थी, हम ‘‘सबका विकास’’ में विश्वास रखते हैं’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष संवाद में विकसित राजस्थान की रूपरेखा पर चर्चा की



## विकास के संकल्प पर सांसद-विधायक संवाद

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा के जनप्रतिनिधियों और जिला अध्यक्षों से संवाद किया।

जयपुर, 26 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और भाजपा जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश के विकास पर संवाद किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि जन आकांक्षाएं राज्य सरकार के विजन का केन्द्र बिन्दु हैं। हमारी सरकार ने बजट में सभी 200

■ मुख्यमंत्री ने कहा, कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी विरासत हैं। यदि हम इनका संरक्षण व संवर्धन कर टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से विकास करें तो पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा व स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

विधानसभा क्षेत्रों के लिए बिना किसी भेदभाव के बजट का प्रावधान किया है। हमारी सरकार सबका साथ-सबका विकास में विश्वास रखती है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार कमीशन के लिए काम करती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हमारी विरासत हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि

विरासत और विकास दोनों साथ चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में घरेलू पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यदि हम इन हवेलियों का संरक्षण और संवर्धन कर टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से इनका विकास करें तो इससे पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को

रोजगार मिलेगा।

शर्मा ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों को केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं से लाभान्वित करें।

इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) को धरातल पर शुरू किया। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दिया है।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान वे पूरी तैयारी कर सदन में होने वाली चर्चा में भाग लें।

## मोदी ने ट्रंप के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तो हाल के हफ्तों में ट्रंप द्वारा चार बार फ़ोन कॉल करने के बावजूद मोदी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में उन सटीक तारीखों का ज़िक्र नहीं किया गया है जिन पर कथित तौर पर कॉल किए गए थे। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, भारतीय अधिकारियों ने इन कॉल्स पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

## एससीओ समिट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महत्वपूर्ण रक्षा मुद्दों को संबोधित करने में एससीओ विफल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस मंच पर भी झलकता है। जून में हुए एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने हिंदू पर्यटकों पर हमले का ज़िक्र न होने पर आपत्ति जताई, जिससे संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। भारत ने ईरान पर इज़रायली हमले की निंदा करने वाले एससीओ बयान में भी शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालाँकि भारत-चीन संबंधों में हाल ही में आई नरमी और ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर नए टैरिफ़ दबाव ने इस बार शी-मोदी बैठक से सकारात्मक उम्मीदें जगा दी हैं। हरिक ओलेंडर के अनुसार, “संभव है कि भारत अपनी प्रतिष्ठा को थोड़ा पीछे रखकर इस साल के एससीओ विवादों को धुला दे, क्योंकि चीन के साथ संबंध सुधारना मोदी की वर्तमान प्राथमिकता है।” ट्रंप के रुख से आहत मोदी जान गए हैं कि भारत के पास कूटनीतिक दांव के विकल्प सीमित हैं। इसलिए मोदी सरकार ने विदेश नीति के अन्य विकल्प तलाशने का निर्णय किया है चीन से हाथ मिलाना इसी का अंग है। बीजिंग भारत की दुविधा को समझता है और उसकी गणना में भारत के अमेरिका के पाले में जाने से अच्छा है स्वतंत्र व तटस्थ भार उसके पास आ जाए। विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारत और चीन सीमा से सेना हटाने, व्यापार और वीजा नियमों में ढील, जलवायु सहयोग, और जन-संपर्क को बढ़ाने जैसे कई छोटे कदमों की घोषणा कर सकते हैं। हालाँकि इस सम्मेलन से बड़े नीति निर्णयों की उम्मीद नहीं है, फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके प्रतीकात्मक महत्व को कम करके नहीं आँकना चाहिए। ओलेंडर के शब्दों में, यह शिखर सम्मेलन प्रतीकों के बारे में है और बहुत शक्तिशाली प्रतीकों के बारे में। सम्मेलन के बाद मोदी चीन से रवाना हो जाएंगे, जबकि पुतिन बीजिंग में होने वाली द्वितीय विश्व युद्ध की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए सप्ताहभर चीन में रहेंगे - जो रूस के बाहर उनका एक असाधारण रूप से लंबा दौर होगा।

# हैल्थ इंश्योरेंस और...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर जीएसटी को शुल्क कर दिया जाए। अब यह रिपोर्ट परिषद के पास है, जहाँ अंतिम निर्णय राज्य के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार के हाथ में होगा। कुछ वैकल्पिक सुझाव भी विचाराधीन हैं - जैसे जीएसटी को आंशिक रूप से घटाकर 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत करना, या वरिष्ठ नागरिकों अथवा 5 लाख तक की पॉलिसियों के लिए राहत देना। ये आधे-अधूरे उपाय सरकार को राजस्व में अधिक नुकसान से तो बचा लेंगे, लेकिन बीमा को वास्तव में सुलभ बनाने के उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं।

राज्यों की अपनी चिंताएँ जायज़ हैं। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से हर साल 2,600 करोड़ से 9,700 करोड़ तक का राजस्व आता है, जो छूट के दायरे पर निर्भर करता है। ऐसे समय में जबकि, कई राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, इस राजस्व को छोड़ना आसान नहीं होगा। बीमा कंपनियों भी चिंतित हैं। अगर जीएसटी हटा दिया गया, तो उन्हें अपनी सेवाओं पर मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इन मुद्दों पर परिषद में तीखी बहस की संभावना

है। फिर भी, छूट के पक्ष में दलील बहुत मजबूत है। भारत के पक्ष में समय से बीमा की कम पहुँच और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। इसका मतलब है कि बीमारी के समय या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार अपनी बचत पर निर्भर रहते हैं। जीएसटी को हटाकर सरकार की तरफ से यह संकेत जाएगा कि वह बीमा के जरिए लोगों को जोखिम बाँटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। जिससे परिवारों की वित्तीय असुरक्षा कम होगी। यह वित्तीय समावेशन (फायनैशियल इन्क्लूजन) और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यापक नीति के अनुरूप भी है।

इस निर्णय का समय भी बहुत अहम है। जीएसटी परिषद की सितंबर बैठक में टैक्स स्लैब्स को बदलकर उन्हें आसान बनाने की संभावना है। इसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब हटाकर सिर्फ़ दो दरें, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव है। इस व्यापक सुधार के बीच बीमा पर छूट सबसे ज्यादा उपभोक्ता-हितैषी कदम के रूप में उभर सकती है। सरकार इसे दिवाली तोहफे के रूप में पेश कर सकती है, और इसे अक्टूबर में त्योहारी सीजन

से पहले लागू किया जा सकता है। इससे बीमा कंपनियों को अपने उपादों की कीमतें फिर से तय करने और बाज़ार में उन्हें अधिक आकर्षक बनाने का मौका मिलेगा।

अंततः यह मुद्दा इस पर निर्भर करता है कि परिषद वित्तीय विवेक और सामाजिक ज़रूरत के बीच संतुलन कैसे बनाती है। भारत की बचत प्रणाली पहले ही बदल रही है, लोग अब सोना और अचल संपत्ति के बजाय वित्तीय साधनों में निवेश कर रहे हैं।

सुरक्षा (प्रोटैक्शन) की लागत को कम करना इस प्रवृत्ति को और मजबूत करेगा। यह एक ऐसा समाज बनाने में मदद करेगा जो ज्यादा स्वस्थ और आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, जहाँ बीमारी या अकाल मृत्यु से लोग कम प्रभावित हों।

अगर परिषद यह साहसिक निर्णय लेती है और पूर्ण छूट देती है, तो यह सुधार जीएसटी के लागू होने के बाद से उपभोक्ता हित में लिए गए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में गिना जाएगा। यह दिखाएगा कि टैक्स सिस्टम केवल राजस्व जुटाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति को सक्षम बनाने के लिए भी है।

## आप नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी का छापा

नयी दिल्ली, 26 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 24 अस्पतालों के निर्माण से जुड़े 5,590 करोड़ रुपये के घनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर सहित 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ईडी सूत्रों ने कहा कि फिलहाल तेरह स्थानों पर तलाशी चल रही है। घन शोधन निवारण (पीएमएलए) मामला 2018-19 में हुए कथित

दिल्ली अस्पताल निर्माण से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि निर्माण में देरी होने के कारण अस्पतालों की लागत बढ़ गई। 2018-19 में आप सरकार के अस्पतालों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी, हालाँकि परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

## राहुल की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी

पटना, 26 अगस्त। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा आज बिहार में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा में अपने भाई राहुल गांधी के साथ शामिल हुईं। यात्रा के दसवें दिन सुपौल जिले में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पहली बार प्रियंका गांधी इस अभियान में शामिल हुईं और राहुल गांधी के साथ खुले वाहन में लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान माहौल उत्साहपूर्ण रहा और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति देखी गई।

## अमेरिका ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किए जाएंगे या गोदाम से निकाले जाएंगे। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत के सामान पर टैरिफ को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा की थी, जो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया जा रहा है। अमेरिका की यह समयसीमा 27 अगस्त को खत्म हो रही है।

**MARUTI SUZUKI**

# BALENO के साथ, हर राह आसान।

इस गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता के आशीर्वाद और बलेनो की शानदार सवारी से हर चुनौती को पार करें।

**10 YEARS OF BALENO**

**REGAL EDITION**  
GET COMPLIMENTARY PACKAGE OF UP TO ₹ 51 480<sup>^</sup>

**THE NEW AGE BALENO**  
TECH GOES BOLD

360 व्यू कैमरा

श्रेणी में पहला

हेड अप डिस्प्ले

हर मॉडल में 6 एयरवैग ~

इन-बिल्ट सुजुकी कनेक्ट

DRIVE HOME THE BALENO AT JUST ₹4 999<sup>#</sup> per month.

## ₹ 1 17 100\*\* तक के लाभ

## कीमत ₹ 6.74 लाख<sup>^</sup> से शुरू

मान्य प्रमाणपत्र जमा करने पर अतिरिक्त स्कैपेज बोनस उपलब्ध है

स्कैन करें और निकट के शोरूम से जुड़ें

आज ही ई-बुक करें @ [WWW.NEXAEXPERIENCE.COM](http://WWW.NEXAEXPERIENCE.COM)

हमसे यहां संपर्क करें

**1800-200-[6392]**  
**1800-102-[6392]**

**BIKANER: NEXA JAIPUR ROAD (AURIC MOTORS PH: 7230081665), NEXA GANGANAGAR ROAD (VIPUL MOTORS PH: 9257041501) JHUNJHUNU: NEXA JHUNJHUNU CENTRAL (AURIC MOTORS PH: 7412087314), CHIRAWA: NEXA PILANI ROAD (AURIC MOTORS: 8875012681), SUJANGARH: NEXA CHHAPAR ROAD (AURIC MOTORS: 8875011580).**

<sup>^</sup> विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाएं. ऑफ़र सरीदे गए मॉडल और वैरिएंट के आधार पर भिन्न हो सकते हैं. <sup>\*\*</sup> सभी ऑफ़र केवल NEXA डीलरों द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं. <sup>^</sup> मारुति सुजुकी लिमिटेड किसी भी समय ऑफ़र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है. रचनात्मक प्रस्तुति. <sup>\*</sup> एयरवैग सहित सूक्ष्म सुविधाओं के काराकाज के विवरण के लिए, कृपया उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें. <sup>+</sup> 3 साल या 100000 किमी. जो भी पहले हो. <sup>^</sup> EMI @ ₹ 4999 माहक अपग्रेड (एग्रीमी कार का एक्वाइजिशन मूल्य 3.40 लाख रुपये) बलेनो सिग्ना वैरिएंट में करने के लिए एक स्क्रीम है. बैलूत फ़ाइनैस EMI की गणना 9.5% ब्याज दर पर की जाती है. बैलूत EMI कुल लोन राशि का 30% और 5 वर्ष की लोन अवधि है. बैलूत फ़ाइनैस स्क्रीम बुनियादी फ़ाइनैसों द्वारा प्रदान की जाती है. फ़ाइनैस के निर्णय पर फ़ाइनैस किया जाता है और ग्राहक की प्रोफ़ाइल के आधार पर भिन्न हो सकता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने निकटतम नेक्सा डीलर या टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें.